संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत और भारत में व्यवसाय और मानवाधिकार

भारत में व्यापार और मानवाधिकार (बीएचआर) की स्थिति की समीक्षा

व्यावसायिक अधिकारों के लिए भूमि

भारत में भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, लेकिन इसकी आधी से अधिक आबादी के लिए आजीविका का एक स्रोत है। भारत की औसत भूमि (तीन एकड़ या उससे कम), अमेरिका (चार सौ पचास एकड़), फ्रांस (एक सौ दस एकड़) या ब्राजील (-) और अर्जेंटीना (पांच हेक्टेयर) से कम है। यह लगभग चीन के समान है (दो हेक्टेयर या उससे कम)। भारत में कृषि सबसे कम उत्पादक है, जो भारतीय जीडीपी का पंद्रह प्रतिशत है। लेकिन यह कुल आबादी का लगभग आधा है। यह भारतीय गरीबी का एक प्रबल कारण हो सकता है। इसलिए, कृषि को या तो अधिक कुशल बनाने की ज़रूरत है या कहीं और उपयोग करके भूमि को अधिक उत्पादक बनाने की ज़रुरत है| भारत की वृद्धि और विकास के लिए संयुक्त कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ शहरीकरण के लिए एक बड़े पैमाने पर सरकारी प्रयास बहुत ज़रूरी नुस्खा था। लेकिन दोनों मामलों में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। उनीस सौ चौरासी से भूमि अधिग्रहण कानून ने भूमि-प्रतिरोध और विवादित भूमि-खिताबों की समस्या को दूर करने के लिए भूमि जोतों के विखंडन से निपटारा किया। लगभग पचास मिलियन लोगों को प्रभावित करते हुए, उनीस सौ सैंतालीस के बाद से भारत की कुल भूमि का छह प्रतिशत से अधिक अधिग्रहण किया गया है। ज़मींदारों को बहुत कम भुगतान किया गया और किसानों और किसानों के हितों को चोट पहुंचाई गई । बहुत कम पुनर्वास का आयोजन किया गया था, और आदिवासी सबसे ज्यादा पीड़ित थे। अधिग्रहण कानून को भौगोलिक और आर्थिक विविधता और इसकी विशिष्ट स्थानीय भूमि संस्कृतियों और इतिहास को स्वीकार करने की आवश्यकता है।

श्रम और मानव अधिकार

असंगठित क्षेत्र के ज़्यादातर मज़दूर गरीब हैं। श्रम ठेकेदारों से लिए गया ऋण उन्हें बंधुआ मजदूर बनने के लिए मजबूर करते हैं । असंगठित क्षेत्र में, मजदूर अक्सर अपने कानूनी दायित्वों से अंजान होते हैं। यह उन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उन्नीस सौ अड़तालीस के लाभ से वंचित करता है। बंधुआ मजदूरी की तरह , भारत में एक प्रचलित श्रम पद्धति उद्योगों के कर्मचारियों की संख्या में शामिल होने वाले बच्चों पर निर्भर करती है। हालांकि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, उन्नीस सौ छिहत्तर और बाल श्रम (संरक्षण और रोकथाम) अधिनियम, उन्नीस सौ छियासी जैसे निर्देश मौजूद हैं, सरकार के लिए उन्हें सक्रिय रूप से बनाए रखना और उनको लागू करना सुनिश्चित करना ज़रूरी है। श्रम का अंतरराज्यीय स्थातान्तरण रोजगार के लिए अधिक गुंजाइश सुनिश्चित करता है। लेकिन हिंसक कट्टरपंथी सामाजिक-राजनीतिक दलों की उपस्थिति ने आपूर्ति-खपत के अंतर को पूरा करने के लिए कुशल प्रवास को साधन बनाया है । इसलिए, श्रम को अंतर-राज्य प्रवासी कार्यकर्ता(रोजगार और सेवाओं की स्थिति का विनियमन) अधिनियम, उन्नीस सौ उन्यासी के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसीआई) मानव और व्यावसायिक अधिकारों को बनाए रखता है। यह राज्य के कर्तव्य की रक्षा करने और पीड़ितों को उपचार तक पहुंच सुनिश्चित करने के कर्तव्य को पहचानता है। दो हज़ार छह में छियासी प्रतिशत भारतीय कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थे, अन्य छह दशमलव दो प्रतिशत अनौपचारिक रूप से कार्यरत थे। इस दशक में कुछ भी नहीं बदला है, जहां क्षेत्रीय भार अभी भी औसतन तिरासी प्रतिशत है। नियोक्ता दावा करते हैं कि वे व्यापार और उद्योग संघों द्वारा अपनाई गई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के वायदों को बर्दाश्त नहीं कर सकते । इसलिए कॉर्पोरेट जिम्मेदारी (औपचारिक क्षेत्र) के तहत कर्मचारियों की संख्या मात्र दस प्रतिशत है।

बीएचआर और संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत

यूएनजीपी की समीक्षा

कॉरपोरेट जिम्मेदारी व्यवसायों और मानवाधिकारों के विचारों की एकता को बनाए रखने में सहयोग करती है। व्यवसायों के प्रभावों का समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जॉन रग्गी के आदेश के तहत दो हज़ार पांच और दो

हज़ार ग्यारह के बीच विकसित 'रक्षा, सम्मान और उपाय के ढांचे' का समर्थन किया । वे व्यापार और मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि थे।

मार्गदर्शक सिद्धांत विस्तृत खोज और दुनिया भर में लगभग पचास अंतरराष्ट्रीय परामर्शों के बाद बनाए गए थे । समर्थन के बाद, बीएचआर पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह, जिसमें पांच स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं, को यूएनजीपी के परिपालन का मार्गदर्शन करने के लिए सौंपा गया था। ढांचा असमान रूप से राज्य के कर्तव्य को मान्यता देता है कि वह कॉर्पोरेट उद्यमों द्वारा किए गए उल्लंघन से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत हर किसी की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को बनाए रखे। व्यवसायों की कॉर्पोरेट जिम्मेदारी है कि वे जहां भी और जब भी काम करते हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे | ढांचा, कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों से उनकी क्षमता और वास्तविक प्रभावों पर जागरूकता की मांग करता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी राज्य के कर्तव्य से अलग होनी चाहिए। व्यापार से सम्बंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने और संबोधित करने के लिए यहां राज्यों के पास प्रभावी कानूनी साधन और नियम होने चाहिए।

मार्गदर्शक सिद्धांतों के तीन स्तंभ हैं: रक्षा, सम्मान और उपाय। प्रत्येक स्तंभ मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करने के लिए सरकार और कॉर्पोरेट कर्तव्य के पहलुओं पर उठाए जाने वाले ठोस व्यक्तिगत कदमों से निपटता है (यहाँ कृषि श्रम बल के लाभ के लिए भूमि अधिकारों को शामिल करने की एक गहन आवश्यकता है),

रक्षा के लिए राज्य का कर्तव्य

संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक बुनियादी सिद्धांत अपने क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र के भीतर मानवाधिकारों को उल्लंघन से बचाने के लिए राज्यों के कर्तव्य पर चर्चा करता है। स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनी दायित्वों के अनुसार एक राज्य को अपनी संस्थाओं के मानवाधिकारों के (i) सम्मान, (ii) सुरक्षा, और (iii) तृतीय पक्ष संगठनों (व्यावसायिक उद्यमों सहित) द्वारा दुरुपयोग का पालन करना है| यदि कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला शासनादेश (अक्सर निजी अभिनेताओं) का उल्लंघन करता है तो यह राज्य की जिम्मेदारी नहीं होती है| लेकिन उनके अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनी दायित्वों का उल्लंघन होने पर, पीड़ितों

की रक्षा के मामले की देखरेख करना उनका कर्तव्य है। क्षेत्र में व्यवसायों की सर्वोत्तम कार्यक्षमता के लिए निर्धारित नियमों के अनुरूप व्यवसाय उद्यम की रक्षा करना एक राज्य की जिम्मेदारी होती है। यदि व्यवसाय उचित मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए बीएचआर ढांचे के आधार पर नाकामयाब होता है, तो राज्य आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होता है। "राज्यों को अपने उद्यमों और / या अधिकार क्षेत्र में , तृतीय पक्षों, जिसमें व्यावसायिक उद्यम भी शामिल हैं, के द्वारा मानव अधिकारों के दुरुपयोग से रक्षा करनी चाहिए | इसके लिए प्रभावी नीतियों, कानून, विनियमों और अधिनिर्णय के माध्यम से इस तरह के दुरुपयोग को रोकने, जांच, दंडित और निवारण के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। " अतिरिक्त मामलों में जहां एक दुर्व्यवहार के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या जहां राज्य आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाने में नाकामयाब रहा है (रोकथाम, जांच, दंड और निवारण), राज्य सीधे मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है।

सम्मान के लिए कॉर्पोरेट जिम्मेदारी

मार्गदर्शक सिद्धांत ग्यारह के अनुसार "व्यावसायिक उद्यमों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें दूसरों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचना चाहिए और मानव अधिकारों के विपरीत प्रभाव, जिसमें वे शामिल हैं, को संबोधित करना चाहिए, । " उद्यमों को, यदि वे किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो दैनिक आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सिद्धांत संचालन के क्षेत्र में बुनियादी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को महत्त्व देता है, क्योंकि व्यवसाय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से श्रम को प्रभावित करता है। व्यवसाय अक्सर स्वैच्छिक रूप से उन कर्मचारियो के श्रम अधिकारों की सुरक्षा करने में अतिरिक्त ज़िम्मेदारी लेते हैं जिन्हें या तो वे स्वयं सेवा में लगाते हैं या जो किसी भी क्षमता में इन निगमों से जुड़े होते हैं। कॉरपोरेट ज़िम्मेदारी का पालन करने में असफल होना भी लंबे समय में राज्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की स्थिति में मानवाधिकारों का उल्लंघन भी मानव अधिकारों के रक्षक के रूप में राज्य के कामकाज के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर व्यापार सबूतों को बाधित करता है या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करता है तो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (उपाय के लिए एक राज्य द्वारा संचालित साधन) भंग हो सकता है । मार्गदर्शक

सिद्धांत राज्य को न्याय प्रदान करने की एक तृतीयक भूमिका प्रदान करते हैं। बीएचआर को बनाए रखने के लिए मुख्य पार्टी कॉर्पोरेट व्यवसाय है।

बीएचआर का उद्देश्य

बीएचआर और भारत

दो जून दो हज़ार सत्रह को, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कोलकाता में व्यावसायिक मानवाधिकार पर पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और मानव अधिकारों के क्षेत्र के विकास को साझा करना और हिस्सेदारों के विचारों पर विचार-विमर्श करना था। सार्वभौमिक उपलब्धता और मानवाधिकारों की पहुंच की प्रासंगिकता पर चर्चा की गई। न्यायमूर्ति दमार मुरुगेसन (एनएचआरसी के सदस्य), डॉ। सत्य मोहंती (एनएचआरसी के महासचिव) और श्री सुशांत सेन (सीआईआई के प्रमुख सलाहकार), औद्योगिक संबंधों के महत्व, नियमित और अनुबंध मज़दूरो की गरिमा और उचित मजदूरी वितरण की महत्वता को उजागर करती हाल में की गयी पहल के के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए। जॉन रग्गी द्वारा विकसित व्यापार और मानव अधिकार पर यूएनजीपी को दो हज़ार ग्यारह में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा समर्थन के बाद सम्मेलन के दायरे में लाया गया। तीन स्थित स्तंभों की भूमिकाएं: संरक्षण, सम्मान और बचाव, पर विस्तृत रूप से बहस की गई।

यह एक तथ्य है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ लोगों की सुरक्षा के लिए पहल करना सरकार की जिम्मेदारी है| साथ ही, व्यवसायों को अपने निजी लाभ को अधिकतम करने के लिए मानव अधिकारों के दुरुपयोग के लिए खुद को जवाबदेह रखने की आवश्यकता है । यह महत्वपूर्ण है कि व्यवसायों के आचरण और संचालन को देश की मानवाधिकार संस्कृति का सम्मान करना चाहिए।

हाल के दिनों में, एनएचआरसीआई ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के साथ "व्यापार और मानवाधिकार" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मानवाधिकारों की रक्षा और कॉरपोरेट जिम्मेदारी को बनाए रखने के लिए राज्य के कर्तव्यों के बबरे में चिंतन किया गया। भारत में एनएचआरसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो

बीएचआर से संबंधित है। इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (सीएफएनएचआरआई) के राष्ट्रमंडल मंच द्वारा इस विषय के लिए केंद्र बिंदु नामित किया गया है। इसलिए आयोग ने व्यापार और उद्योग संघों के साथ एक बैठक की व्यवस्था की ताकि व्यापार उद्यमों के साथ जुड़ाव का मानचित्र तैयार किया जा सके। इसके बाद व्यापार द्वारा मानव अधिकारों के सिद्धांतों के स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग संघों / संगठनों के साथ कई बैठकें की गईं। इसने स्व-मूल्यांकन उपकरण के प्रारूप को जन्म दिया जो स्वेच्छा से उद्योग द्वारा उपयोग किया जाना था। इसके बाद दो हज़ार सत्रह में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। मानवाधिकार कंपनियों के लिए एक स्वैच्छिक दायित्व है, भले ही यूएनजीपी अमल करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो। हालांकि भारत में यूएनजीपी अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हैं, कई संगठन जैसे कि एथिकल ट्रेड इनिशिएटिव (ईटीआई) सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और एक बाध्यकारी ढांचे के अमल और संचालन पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। यह विचार यूएनजीपी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियमो के व्यवसाय उद्यमों के अनुरूप निगरानी के लिए संकेतकों के बारे में जागरूकता और विकास को बढ़ाने के लिए है।

यूएनजीपी पर जागरूकता का निर्माण

व्यापार कार्यों और भारत में नागरिक अधिकारों के बीच बेमेल आंशिक रूप से उपाय करने की पहुंच की कमी और जागरूकता की कमी के कारण है। जबकि भारतीय संविधान मानव अधिकारों का दृढ़ता से समर्थन करता है, एनएचआरसीआई अक्सर कार्य करने में नाकामयाब रहा है। एनएचआरसीआई नियमित रूप से अपने कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। यह संरचना, बनावट, निर्णय लेने और संचालन विधियों में सरकार की पेरिस सिद्धांतों की स्वतंत्रता के बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकामयाब रहा। संवाद के माध्यम से सूचना विषमता को भरने की जरूरत है। ईटीआई द्वारा परिवर्तन के लिए संवाद सम्मेलन में विभिन्न कॉर्पोरेट हितधारकों - सरकार, नागरिक समाज और व्यवसायों के दृष्टिकोण आपस में टकराए। इन संवादों से निम्नलिखित में जागरूकता बढ़ती है:

1. यूएनजीपी के बारे में हितधारकों को शिक्षित करना
2. व्यापक रूप से मानवाधिकारों और उनके दुरुपयोग पर चर्चा |

3. मानव अधिकारों के विचारों के कारण प्रभावशाली व्यावसायिक निर्णय और उनके वित्तीय नतीजे|

4. व्यवसाय और मानवाधिकारों के बीच एक नवीन ढाँचे की दिशा में उद्यमों को बढ़ावा देना|